एन एफ टी ई (NFTE-BSNL) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (NEC) के प्रस्ताव पटना में 14-03-2026 से 15-03-2026 तक अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड सी.के. मथिवनन की अध्यक्षता में आयोजित NEC की बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव अपनाए गए:

1. संगठनात्मक मामले * सम्मेलन: संघ के संविधान के अनुसार, सर्कल और जिला यूनियनों को समय-समय पर अपने सम्मेलन आयोजित करने होंगे। यदि कोई यूनियन अनुरोध के बाद भी सम्मेलन नहीं करती है, तो NEC ने मुख्यालय (CHQ) को बिना किसी देरी के संवैधानिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया है। * प्रतिनिधित्व: यदि कोई सर्कल या जिला सचिव बैठक में शामिल नहीं हो पाता है, तो उनकी जगह एक सहायक सचिव को प्रतिनिधित्व के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए।

2. तीसरा वेतन संशोधन (3rd Wage Revision) * कार्यान्वयन: NEC ने 01-01-2017 से तीसरे वेतन संशोधन को तुरंत लागू करने की मांग की है, क्योंकि इसका समझौता प्रबंधन के साथ 08-10-2025 को ही हो चुका है। * छूट की मांग: सरकार से अपील की गई है कि BSNL के लिए 'सामर्थ्य' (Affordability) और 'लाभप्रदता' की शर्तों में ढील दी जाए, ताकि पिछले 9 वर्षों से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे कर्मचारी ठहराव (stagnation) से बाहर आ सकें।

3. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS-2) का विरोध * कर्मचारियों की कटौती: NEC ने VRS-2 के नाम पर कर्मचारियों की संख्या में और कमी करने का कड़ा विरोध किया है। * तर्क: बजट 2026-27 में BSNL/MTNL के लिए ₹28,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो तकनीक विकास के लिए भी हैं। 2019 के VRS में पहले ही 77,000 कर्मचारी कम हो चुके हैं; अब और कटौती से 4G/5G सेवाओं के विस्तार और BSNL के पुनरुद्धार पर बुरा असर पड़ेगा। * समय सीमा: प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कर्मचारी कटौती के लिए 31-10-2026 की समय सीमा तय करने की जानकारी पर संघ ने चिंता व्यक्त की है और सभी यूनियनों के साथ मिलकर इसका विरोध करने का निर्णय लिया है।

4. मोबाइल फोन भत्ता * मांग: सभी गैर-कार्यकारी (Non-executive) कर्मचारियों को मोबाइल खरीदने के लिए ₹5,000 की एकमुश्त राशि दी जाए। * कारण: वर्तमान में उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होती है, जिसके लिए एंड्रॉइड फोन अनिवार्य है। अधिकारियों को इसके लिए राशि मिलती है, लेकिन गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के साथ यह भेदभाव खत्म होना चाहिए।

5. नई पदोन्नति नीति (NEPP) * विसंगतियां: 2006 की मौजूदा नीति में कई खामियां और भेदभाव हैं। * एकजुटता: अब NFTE और BSNLEU दोनों यूनियनें मिलकर अधिकारियों के समान नई पदोन्नति नीति की मांग कर रही हैं। प्रबंधन द्वारा समिति की रिपोर्ट पर कोई सार्थक चर्चा न करने के कारण, NEC ने इसे तुरंत लागू करने की मांग की है।

6. दसवीं सदस्यता सत्यापन (10th Membership Verification) * देरी: 10वां सदस्यता सत्यापन 2025 में ही देय था, जिसे प्रबंधन तदर्थ (adhoc) रूप से टाल रहा है। * तरीका: प्रबंधन ने खर्च बचाने के लिए 'चेक ऑफ' पद्धति का प्रस्ताव दिया है। * शर्त: NFTE इस पद्धति को केवल तभी स्वीकार करेगा जब प्रबंधन 50% समर्थन वाली शर्त हटाकर दो यूनियनों की मान्यता के नियमों में संशोधन करे। यदि प्रबंधन नहीं मानता, तो संघ 'सीक्रेट बैलेट' (गुप्त मतदान) की मांग करेगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी रास्ता अपनाएगा।